



प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITE

Ho 39]

नई दिल्ली, शनिवार, सिलम्बर 25, 1993 (अश्विन 3, 1915)

REGISTERED NO. DL -33001

No. 39]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1993 (ASVINA 3, 1915)

इस माग में भिन्न पृथ्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

	चिष्य	-स्चा	
भाग I—स्वण्ड 1—स् (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंक्षालयों और उच्चतम स्प्रायालय द्वारा जारी की गई विधित्तर नियमों, विनियमों, अवेशों	পুণ্ঠ	भाग IIखण्ड 3उप-खण्ड (iii)भारत सरकार के मैत्रालयों (जिनमें रक्षा मैत्रालय भी गामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संग गासित क्षेत्रों के	पृष्ठ
तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं भाग ! — खण्ड 2 — (रक्षा मंद्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंद्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के	721	प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामाध्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपक के	
संबंध में अधिसूचनाएं	989	श्राण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग I खण्ड 3 रक्षा भंजालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों भीर असोविधिक आदेशों के संबंध में अधि- सूचनाएं	ď	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंद्रालय द्वारा जारी किए गए सीविधिक नियम और आदेश	*
भाग 1	5	भागा∏—-खण्ड 1—-उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महासेखा- परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग	
छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं ' भाग II	1679 *	और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	915
माय II—विष्य 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ माय II—विष्य 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों	*	भाग III — खण्ड 2 — पेटेंग्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंग्टों और डिजाइमों से लंडिया अधिसूचनाएँ	
के जिल सथा रिपोर्ट	*	औरनोटिस 🖁 🔭 🐈	825
माग II - खण्ड 3 - उप-खण्ड (i) - मारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		भाग IIIचण्ड 3मुक्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीत] अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .*	•
प्राधिकरणों (स'घ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वकप के आदेश और उपविक्षियों शादि भी शामिल		भाग 🌃 — खण्ड 4 — विविध अविसूचनाएँ जिनमें साविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैंं	15753
(i) · · · · ·	*	भाग IVगैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञानन और	
साम 11 - अप्य 3 - उप-वण्य (ii) - भारत सरकार के मंत्रालयों (रका मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संव शासित खक्षों के प्रशासनों		।तकाय। द्वारा जारा उक्तर गर् विकास कार नोटिस	135
को छोक्कर) द्वा ^ध जारी किए गय् यां विद्यिक आदेश सीर अधिसूचनाएं	76	भाग V— श्रेष्ठेंची श्रीर हिस्सी होते हो अस्म हैंसीर सस्य के श्रांबाड़ी की बनाने बाला अनुपूरक •	Section of the sectio
A CONTRACT WATER			

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION (—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court. PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other	72	Part II —Section 3—Sub-Sec. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazotte of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	•
than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court PART I—SECTION 3—Notifications relating to Reso-	989	PART II —Secrem 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	•
lutions and Non-Statutory Orders Issued by the Ministry of Defence PART I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers Issued by the Ministry of Defence PART II—Section 1—Acts, Ordinances and Regula-	5 1689	PART III —Section 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	915
tions PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	•	PART III —Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	825
PABT II—Section 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills PART II—Section 3—Sub-Section (I)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-	•	PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	•
laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Contral Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART III —Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	15753
PART II—Section 3—Sus-Section (II)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART IV —Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bo lies	135
by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	•	PART V —Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	•

भाग । ---- खण्ड 1

[PART I-SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्वतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विस मंद्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अगस्त 1993

संकल्प

सं ० 11011/3/92—हि० का० क०—इस विभाग के दिनांक 7 जनवरी और 12 जुलाई 1993 के समसंख्यक संकल्प के किम में आधिक कार्य विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति (बैंकिंग तथा बीमा सहित) में गैर-सरकारी सदस्य के रूप में श्री अरविन्य चतुर्वेदी 69—भविष्य निधि इंक्लेव, मालवीय नगर, नई विल्ली-110017 को नामित किया जाता है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निदेशक, केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचतार्थ इस संकल्प को भारत के राजन्त में प्रकाशित किया जाए।

> एन के० सिंह अपर सचिव

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई विल्ली, दिनांक 16 अगस्त 1993

आदेश

विषय :---तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कृष्णा-गोदावरी (अपतटीय) क्षेत्र में ब्लाक आई० डी०
क्षेत्र 1676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम
अन्वेषण लाइसेंस की पुनः स्वींकृति

सं० ओ०-12012/51/92 ओ० एन जी० डी०-4--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतव्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात आयोग कहा गया है) कृष्णा-गोदावरी (अपतटीय) क्षेत्र में ब्लाक आई० डी० क्षेत्र के 1676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 16 दिसम्बर 1992 (16-12-1992) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में विए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्ती पर है:---

- (क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।
- (ख) यदि अन्वेषण कार्य के वौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (ग) स्वत्व गुल्क (रॉयल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी:--
 - (1) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड फन्डेन्सेट पर 481 रुपए प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर पर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - (2) प्राकृतिक गैंस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार धारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

स्वत्व मुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियस जार प्राकृतिक मैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम
30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल
की माला, केसिंग हैड कन्डेन्सेट और प्राकृतिक
गैस की माला तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने
बाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार
को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख"
में दिए गए प्रपन्न में भर कर देना होगा।

- (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000 रुपए की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।
- (च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुरुक का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलो-मीटर या उसके किसी अंग के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा निम्नलिखित वरों पर की जाएगी:—
 - (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए---8/- रुपये।
 - (2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए--40/- रुपये।
 - (3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए--200/- रुपये ।
 - (4) लाइसेंस के चतुंर्य वर्ष के लिए---400/- रुपये।
 - (5) लाइसेंस के नवीनीफरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए----600/- रुपये।
- (छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसस में उल्लिखत किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।
- (ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किये जाने पर तत्कास तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भू- वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निष्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना वेगा।
- (झ) आयोग समुद्र की "तलखटी" और "या" उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा नथा आग बुझाने हेतू हर समय के लिए उपकरण सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।
- (ट्रा) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनिमय और षिकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबंध लागू होंगे।

- (ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए ब्यवहार्य होगा।
- (ठ) आयोग खुवाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के वौरान एकत्र किए गए बाथोमीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।
- (ढ) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किये जाते हैं।
- (ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस विया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।
- (त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैय।र की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाईड्रोग्राफ़र को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

अनुसूची ''क''

कृष्णा गोवावरी (अपतटीय) क्षेत्र में ब्लॉक आई डी क्षेत्र के 1676 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांक ।

प्वाहंट	अक्षान्तर	वे मान्तर
ए	16° 15′ 10″	81° 15′ 00″
बी	15° 52′ 54″	80* 45′ 00*
टी	15" 29' 42"	80° 45′ 00″
यू	15° 43′ ·00″	81° 15′ '00″

धनु**ष्**षी "**ष**"

अशोधित तेलं, केसिंग हेड करडेरसेट तथा प्राक्रिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सिंहत माप्तिक वितरण के शिए पेट्रीवियम ग्रन्वेचन लाइसेंस

बेबफल

माहतवा वर्ष

	(क) अधोधित तेल		
हुल प्राप्त मी∘ टन की इंडिया	श्रवरिहार्य रूप से खोये अयवा प्रा∎ितक जलालय को लौटाये मी० टन की सं०	•	कालम 2 मीर 3 की वटाकर प्राप्त मी• टन की संबंधा	বিঅসী
1	2	3	4	5
		(ख) केसिंग हैड कार्ड स्सेट		
प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्यं कप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोबित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी॰ टनों की सं०	कालस 2 और 3 की घटा- कर प्राप्त मी० टन की संख्या	दिप्पणी
1	2	3	4	5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(ग) प्राकृतिक गैस	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	~·
कुल प्राप्त चन मीटरों सी सं॰	अपरिहार्यं रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाक्तय को लौटायें नवे वन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमीदित पेट्रोलियम अम्बेचण कार्य हेतु प्रयोग किये गये चन मीटरों की संख्या	कालम 2 जीर 3 की बटाकर प्राप्त चन मीटरों की संख्या	टिप्प गी
1	2	3	4	5
		_		
		'सत्य निष्ठापूर्वक कोवणा एवं चुरि र मैं सुद्ध जन्तः करण से सर्यनिष्ट		में की गई
			हरताश्र र	• ••
	क्रांच्या के लावालीय के का	केल से समा क्राफी काम ग्रन		-

भारत के राष्ट्रपति के आवेश से तथा जनके नाम पर।

अदिश

विषय :---तेल एवं प्राष्ट्रिक गैस आयोग को कृष्णा, गोदावरी (अपतटीय) क्षेत्र के ब्लाक 1 ई क्षेत्र में 545 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की पुनः स्वीकृति।

सं० भो०-12012/52/92-श्रो० एन० जी० डी०-4-पेट्रोलियम श्रीर प्राइतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राइतिक गैस आयोग, तेल भवन, वेहरादून को (जिसे इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) कुठणा, गोवावरी (अपतटीय) क्षेत्र के ब्लाक 1 ई क्षेत्र में 545 वर्ग किलो-मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अक्षेषण लाइसेंस की 16 दिसम्बर, 1992 (16-12-1992) से चार वर्ष के लिए स्वीकृति वेती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शतौ पर है:--

- (क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।
- (ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य खनिज पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।
- (ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जाएगी:—
 - (1) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 481/-- रु० प्रति मीट्रिक टन ऐसी वर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - (2) प्राक्तिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

स्वस्व मुल्क (रायस्टी) की अवायगी, पेट्रो-लियम श्रीर प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई विल्ली के वेसन तथा लेखा अधिकारी को की जाएगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशो- धित तेल की मात्रा, केसिंग हैं क कन्डेन्सेंट भौर प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपन्न में भर कर देना होगा।

- (क) पेट्रोलियम श्रीर प्राक्षृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 की अपेक्षाश्रों के अनुसार आयोग 50,000/- रुपयं की धनराणि प्रतिभृति के रूप में जमा करेगा।
- (च) आयोग प्रति वर्ष लाइसेंस के संबंध में शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलो मीटर या उसके किसी श्रंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी:---
 - (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए 8/- रुपये।
 - (2) लाइसोंस के ब्रितीय वर्ष के लिए 40/- रुपये।
 - (3) लाइसेंस के सृतीय वर्ष के लिए 200/- रुपये
 - (4) लाइसेंस के वतुर्थ वर्ष के लिए 400/- रूपये।
 - (5) लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और दितीय वर्ष के लिए 600/- रुपये।
- (छ) आयोग को पेट्रोलियम श्रौर प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाश्रों के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतंत्रता सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाद होगी।
- (ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग किये जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से लेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप मे

केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों, व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

- (झ) आयोग समुद्र की "तलहटी" श्रीर या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा श्रीर तीसरी पार्टी श्रीर/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।
- (क्र) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम घौर विकास) अधिनियम, 1948 (1948 का 53) ग्रौर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबंध लागू होंगे।
- (ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।
- (ठ) आयोग/खुदाई/अन्वेषी आपरेशनों/सर्वेक्षणों के बौराम एकझ किए गए वाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा ग्रौर चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (क) आयोग समुद्री विज्ञान ऑकड़ों की सुरक्षा सुनिधिकत करेगा।
- (क) संपूर्ण आंकड़े भारत में संकक्षित किये जाते हैं।
- (झ) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी दल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा । भारत में ऐसे

जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण दल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई सम्पूर्ण प्रति रक्षा मंत्रालय तथा मुख्य ह(इड्रोग्राफर को निगुल्क उपलब्ध करायी जाती है।

अनुसूची ''क''

क्रुप्णा गोदावरी (अपटतीय) क्षेत्र के ब्लॉक 1ई क्षेत्र के 545 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निर्देशांका।

प् वॉइस्ट	अभातर	र वेशांतर
₹सस	1 7° 00′ 00)* 82° 25′ 0 € *
बी	17°00′ 00	D" 82° 16′ 46″
सी	16° 33′ 36	6* 92* 18′ 17 ″
की	16° 33′ 36	8 * 82* 25′ 00 *

प्राप्त किये गये कुल

मी • टन नी सं०

अन्**स्ची**–''**ख**''

अशोधित तेल, केर्सिंग हैंड कल्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सिंहत गासिक वितरण के किए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौडाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय संरकार द्वारा अनुमोक्ति पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यं हेतु प्रयोग किये गये भी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(47)	कासग हुड केन्डरसट		
अपरिष्ठार्यं रूप से खोये	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनु-	कालम 2 और 3 को	टिष्पणी
अथवा प्राकृतिक जलागय	मोदित पेट्रोलियम अन्वेषण	घटाकर प्राप्त मी०	
को लौटाये मी० टन की	कार्य हेतु प्रयोग किये गये	टन की सं०	

1 2 3 4 5

. मी० टनों की सं०

(ग) प्राकृतिक गैस				
कुल प्राप्त वन मीटरों की सं ०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गए घन मीटरों की सं ०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोबित पेट्रोलियन अन्वेषण कार्य हेलु प्रयोग किये गये घन मीटरों की सं०	कालम 2 मौर 3 को घटाकर प्राप्त चन मीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतय्हारा मैं जी ' ' ' ' पूर्व करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण करोण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह कोषणा करता हूं ।

्हस्ताबार---

सं०

इस्पात मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 1993

संकल्प

सं ० ई० 11015 (4) 91-हिन्दी (.)—इस मंत्रालय के दिनांक 13 अप्रैल, 1993 के संमसंस्थक संकल्प के कम में इस्पात मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों को नामित किया जाता है:—

- श्री लक्षमण तिवारी—बी—1/19 ए० एस० एस० आई० वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
- 2 श्री देवी सिंह कछवाहा—रिटायर्ड इन्सपेक्टर आफ़ स्कूल, नागोरी थेरा मंडोर जोधपुर (राजस्थान)।
- 3. श्री सुधाकर प्रसाद राम तिवारी—त्रिपाठी सदन, 265 राजौरी गार्डन अपार्टेमेंट एस० एफ० एम० राजौरी गार्डन, नर्ड दिल्ली—110021।
- मुश्री सुमन लता दीक्षित, भूतपूर्व विधायक-एच० आई० जी०, एल०-32, कुर्सी रोड, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।

आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रि-मंडल संचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक महालेखा—परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम:० के० मोइल्रा संयुक्त सचित्र

नई दिल्लीं, दिनांक 27 अगस्त 1993

संकल्प

सं० 22 (7) 92-टी० डब्स्यू-भारत सरकार ने एकी कृत इस्पात संयंद्वों में परस्पर प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए उनके कार्य निष्पादन में उन्कृष्टता के लिए "प्रधान-मंद्री-ट्रॉफी" नामक पुरस्कार गुरू करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजनार्थ सरकार एतद्द्वारा 1992-93 के लिए एकी कृत इस्पात संयंद्वों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने हेतु निम्नलिखित सदस्यों से युक्त "निर्णायकों का पैनल" गठित करती हैं :---

 श्री मूसा रचा -- अध्यक्ष मचिव, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार

- डा०पी०एल० अग्रवाल सदस्य पूर्व अध्यक्ष, स्टील् अथाँरिटी आफ इण्डिया ुलिमिटेड
- श्री एस० के० भागंव सदस्य उपाध्यक्ष, सी० आई० आई०
- 4. प्रो० रामास्वामी अयुगर —— सदस्य तत्कालीन निदेशक, आई० प्रांई० एम० रुलकत्ता
- डा० प्रणत्र सेन सटस्य सलाहकार, इलेक्ट्रानिकी विभाग
- ७. डा० एन० के० सेन गुप्ता सदस्य पूर्व सचिव,
 थोजना आयोग
- श्री सन्तोष नौदियाल संयोजक संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार
- ,2 निर्णायकों के पैनल की विचारार्थ विषय निम्नानुसार है:---

भारत भरकार द्वारा विनोक 27 अगस्त, 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22(7)/92 टी॰ डब्स्यू के तहत घोषित योजना के अनुसार भारत के सभी एकीक्टल इस्मात संयंत्रों जोपरभ्यरागन कोक ओवन प्रक्रिया घमन भट्टी-इस्पान निर्माण और बेलन मिलों की पद्धित के अनुनार प्रवालनरन हैं, के कार्य का निष्पादन मूख्यांकन करना।

आदेश

अदिश दिया जाता है कि इस संकरन की प्रति सभी सबंधितों को प्रचालित कर दी जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि इस सकरन को सर्वेसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजयब में प्रकाशित किया जाए।

> के > किपगेन संयुक्त समिव

मानव संसाधन विकास मंद्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 जून 1993

सं० एफ > 9-8/89-यू > 3--विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श पर मणिपाल उच्च शिक्षा अकादमी को जिसमें निम्निलिखित शामिल हैं:—

- (क) कस्तूरबा मेडीकल कालेज, मणिपाल और सम्बद्ध शिक्षण हास्पीटल, मणिपाल;
- (ख) बन्त्य शल्य चिकित्यालय मणिपाल;
- (ग) नर्सिंग काक्षेज, मणिपाल ।
- (घ) कस्तूरबा मेडीकल कालेज और सम्बद्ध शिक्षण सस्याएं मंगलोर; और
- (क) बन्त्य शस्य चिकित्सा कालेज, मंगलोर

उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ एक सम-विश्वविद्यालय घोषित करती है।

> डी॰ एस॰ मुखोपध्याय संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली, विनांक 13 अगस्त 1993

संकल्प

सं ० हिन्दी/सिमिति/91/38/1—रेल मंद्रालय (रेलवेबोर्ड) के विनांक 6-2-93 के समसंख्यक संकल्प के कम में श्री कल्याण गर्मा (मकान नं ० 1496/1—ए, गोडुतई कालोनी, भगवती मगर के पास, बस स्टेण्ड केपीछे, गुलवर्गा, कर्माटक) को रेल मंद्रालय के अर्धान गठित रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सबस्य के रूप में नामित किया जाता है।

श्री करूयाण शर्मा के सम्बन्ध में अन्य शर्ते वही होंगी जो 5-2-93 के उपर्युक्त सफल्प में उहिलखित हैं।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस सकस्य की एक-एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय, मंद्रि मंडमडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक मधा तथा राज्यसभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंद्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राज्यत में प्रकाणित किया जाये।

> मसीष्टुज्ज्जमां सम्बद्ध, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

विनांक 16 अगस्त 1993

सं० ई० आर० बी०-1/93/23/19--न्यायाधीश जी० जे० भोजा. सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में गोवा (सयम-बली) से गुजरने वाली कींकण रेलवे लाइन के संरेखण से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन के संबंध में रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) का संकल्प और दि० 3-6-93 का समसंख्यक आदेश देखें।

2. रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने विनिष्चय किया है कि मीजूदा मतौ पर उपर्युक्त समिति की अवधि 15-9-93 तक बढायी जाए।

> मसीहुज्ज्जमां सचिव, रेलवे बोर्ड एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिव

श्रम मंत्रालय

नई विल्ली-110011, दिनांक अगस्त 1993

संकल्प

सं० यू-23011/1/89-डब्ल्यू-II (सी)—संकल्प संख्या यू-23011/1/89-डब्ल्य्-II (सी) दिनांक 12 सितम्बर, 1991 के तहत गठिन अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि संबंधी केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के संघटन, जो भारत के राजपत्र के भाग-I, खण्ड-1 में 12 अक्तूबर, 1991 को पृष्ठ 769-770 पर प्रकाणित हुआ था, में निम्नामुसार संगोधन किया जाता है, अर्थात :—

उक्त संकल्प में, कम संख्या (iii) पर "नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शीर्षक के अंतर्गत की गयी विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

''(iii) श्री डी० के० सिंह, चीफ आफ्र मार्केटिंग, बिहार राज्य खनिज विकास कार्पेरियन चि., खनिज निगम भवन, नेपाल भवन केंद्र, डोरान्डा, रांची—830002"

सथा क्रमांक (iii) पर "क्षमंचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य" शींषक के अंतर्गत की गयी विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिक्थापित की जाएगी, अर्थात् :---

(iii) श्री ईं ० पी ० ए० रशीद, सचिव, यूनाइटेड ट्रेड यूनियम कांग्रेस (नेनिन सरणी), एस० यु० सी० आई० कार्यालय, 7-152, माल्लेश्यरी रोड, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश-515001"

> बी० डी० नागर अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 26th August 1993

No. F. 11011/3/92-HIC.—In continuation of this Department's Resolution of even number dated the 7th January, 1993 and 12th July, 1993 Shri Arvind Chaturvedi, 69 Bhavishaya Nidhi Enclave, Malviya Nagar, New Delhi-110017 is nominated as a non-official member of Hindi Salahakar Samiti for the Department of Economic Affairs (including Banking & Insurance).

ORDER

Ordered that a coy of this Resolution be communicated to:-

All State Governments and Union Territory Administration, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit Central Revenues, all members of Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for General Information.

N. K. SINGH, Addl. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 16th August 1993

ORDER

Subject:—Regrant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Block I D area measuring 1676 sq. kms., in Krishna Godavari. (OFFSHORE)

No. O-12012/51/92-ONG.D.IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehra Dun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 16th December, 1992 (16-12-1992) for Block I Darea measuring 1676 sq. kms., in Krishna Godavari (OFF-SHORE), the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below:—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petro-leum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged:—
 - (i) Rs. 481/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.
 - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.

- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence:—
 - (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
 - (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
 - (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
 - (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
 - (v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.
- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exloration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinquish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation & Development) Act, 1948 (53 of 1948) & the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to Offshore areas as approved by the Central Government.
- (1) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Currend and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.
- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.
- (n) The entire data is precessed in India.
- (o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists/Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.
- (p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area if made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Block I D area measuring 1676 sq. kms., in Krishna Godavari (OFFSHORE).

Point Latitude .					L	ongitu	de
A	16°	15'	10"		81°	15'	00"
B	15°	52'	54"		80°	45'	00"
T	15°	29′	42"	€ ±	80°	45'	00"
U	15°	43'	00*		81°	15'	60"

SCHEDULE 'B'

Monthly return of ocude oil, easing-head condensate and natural gas produced and value thereof. Petroleum Exploration Licence for Area

Month and Year

A-Crude Oil

Tetal No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Govern- ment	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

B-Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Romarine
1	2	3	4	5

C-Natural Gas Number of cubic metres used for pur-Total Number of cubic Metres obtained Number of cubic Number of cubic Remarks metres unavoidably lost metres obtained less columns 2 and 3 poses of petroleum exploration approved by the Central Governor returned to natural reservoir ment 1 2 3 4

By order and in the name of the President of India.

(Signature)

ORDER

Subject:—Regrant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for Block 1 E area measuring 545 sq. kms., in Krishna Godavari (Offshore).

No. O-12012/52/92-ONG. D. IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission), Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 16th December, 1992 (16-12-1992) for Block I E area measuring 545 sq. kms., in Krishna Godavari (Offshore), the particulars of which are given in Schedule

'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :---

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged:
 - (i) Rs. 481/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.
 - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.

- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.
- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the followering rates for such square kilometre or part thereof covered by the licence:—
 - (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
 - (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;
 - (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
 - (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
 - (v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.
- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two months notice in writing to the Central Government

as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinquish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation & Development) Act, 1948 (53 of 1948) & the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to Offshore areas as approved by the Central Government.
- (1) The Commission should render, Bathymetric, bottom samples, Current and magnatic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.
- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.
- (n) The entire data is precessed in India.
- (c) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists/Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.
- (p) A complete set of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of Block I E area measuring 545 sq. kms., in Krishna Godavari (OFFSHORE).

Point	Latitude		Longitude			
X	17° 00	0′ 00″	82°	25′	00"	
В	17° 0	0′ 00″	82°	16′	40″	
\mathbf{c}	16• 3	3' 36"	82°	18′	17,	
D	16° 3	3′ 36″	82°	25'	00"	

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for

Area
Month and Year
A—Crude Oil

Total No. of Metric tonnes obtained	No. of Metric Tonues unavoidably lost or returned to natural reservoir	<u> </u>	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

	BCa:	sing-head condensate		
Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum explo- ration approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

2)	C-	-Natural Gas		
Total No. of cubic metres obtained	No. of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government	No. of ometres obtain less columns 2	
1	2	· 3	4	5

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

M. MARTIN
Desk Officer

MINISTRY OF STEEL

New Delhi, the 22nd June 1993

RESOLUTION

No. E. 11015/4/91-Hindi (.).—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 13th April, 1993, the following non-official members are hereby nominated as member of the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Steel :-

- 1. Shri Laxman Tiwari—B-1/19, A.S.S.I. Varanasi,
- 2. Shri Devi Singh Kachhwaha-Retired Inspector of School, Nagori Bera Mandor Jodhpur (Rajasthan).
- 3. Shri Sudhakar Prasad Ram Tiwari-Tripathi Sadan, 265 Rajouri Garden Apartments S.F.S. Rajouri Garden, New Delhi-110021.
- 4. Ms. Suman Lata Dikshit, Ex. M.L.A.-H.I.G.L.-32, Kursi Road, Aliganj, Lucknow (U.P.).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administration, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. K. MOITRA, Jt. Secy.

New Delhi, the 27th August 1993

RESOLUTION

No. 22 (7)/92-TW.—Government of India have decided to institute an Award to be known as Prime Minister's Trophy for excellence in performance of integrated steel plants to create a sense of competition among them. For this purpose, Government hereby constitute a "Panel of Judges as per composition given below, to evaluate the performance of the integrated steel plants for the year 1992-93.

Chairman

(i) Shrl Moosa Raza Secretary, Ministry of Steel. Govt. of India,

Members

- (ii) Dr. P. L. Agrawal, Ex-Chairman. Steel Authority of India Limited.
- (di) Shri S. K. Bhargava. Vice President, CII.
- (iv) Prof. Ramaswamy Iyer, Former Director, IIM, Calcutta.
- (v) Dr. Pranab Sen, Adviser, Deptt. of Electronics.
- (vi) Dr. N. K. Sen Gupta, Ex-Secretary, Planning Commission.

Convenor

- (vii) Shri Santosh Nautiyal, Joint Secretary, Ministry of Steel, Govt. of India.
- 2. The terms of reference of the panel of judges is as follows :-

To evaluate performance of all integrated steel plants in India operating through the conventional route of Coke Oven-Blast Furnace-Steel Making and Rolling Mills, as per Scheme announced by Government of India vide O. M. No. 22 (7)/92-TW dated 27th August, 1993.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. ORDERED also that the Resolution be published in Gazette of India for general information.

K. KIPGEN, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 1st June 1993

No. F.9-8/89-U.3.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the University Grants Commission, Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the Commission, hereby declare Manipal Academy of Higher Education consisting of :

- (a) Kasturba Medical College, Manipal and associated teaching hospitals, Manipal;
- (b) Colleges of Dental Surgery, Manipal;
- (c) College of Nursing, Manipal;
- (d) Kasturba Medical, College and Associated teaching Institutions, Mangalore; and
- (e) College of Dental Surgery, Mangalore;

as deemed to be a University for the purpose of the aforesaid

D. S. MUKHOPADHYAY, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 13th August 1993

RESOLUTION

No. Hindi/Samiti/91/38/1.—In continuation of the Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution of even number dated 5-2-93. Shri Kalyan Sharma, House No. 1495/1-A, Godutai Colony near Bhagwati Nagar, behind bus stand, Gulbarga (Karnataka) is nominated as non-official member of Railway Hindi Salahkar Samiti constituted under the Ministry of Railways.

The terms and conditions concerning Shri Kalyan Sharma will be the same as mentioned in the above Resolution dated 5-2-93.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat, and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN, Secy., Railway Board & Ex-officio Addl. Secy. to the Government of India

The 16th August 1993

RESOLUTION

No. ERB-I/93/23/19.—Reference Ministry of Railways (Railway Board)'s Resolution and order of even number dated 3-6-93, regarding constitution of a High Level Committee to look into the various issues relating to alignment of Konkan Railway Line passing through Goa (Mayem-Bali) under the Chairmanship of Mr. Justice G. J. Oza, retired Judge, Supreme Court.

2. Ministry of Railways (Railway Board) have decided that the tenure of the above Committee should be extended upto 15-9-93, on the existing terms and conditions.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section-1.

MASIHUZZAMAN, Secy., Railway Board & Ex-officio Addl. Secy. to the Govt. of India

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi-110 011, the 30th August 1993

RESOLUTION

No. U-23011/1/89-W.II (C).—The composition of the Central Advisory Board on Mica Mines Labour Welfare Fund constituted vide Resolution No. U-23011/1/89-W.II (C) dated the 12th September, 1991 published at pages 769-770 of the Gazette of India, Part I, Section 1 dated the 12th October, 1991 is amended as follows, namely:—

In the said Resolution, under the head "Members Representing Employers" at S. No. (iii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(iii) Shri D. K. Singh,
Chief of Marketing,
Bihar State Mineral Development
Corporation Ltd.,
Khanij Nigam Bhavan,
Nepal House Area,
Doranda,
Ranchi-834 002."

and under the head "Members Representing Employees" at S. No. (ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"(iii) Shii E. P. A. Rasheed,
Secretary,
United Trade Union Centre,
(Lenin Sarani),
S.U.C.I. Office,
7-152, Malleswari Road,
Anantapur,
Andhra Pradesh-515 001."

V. D. NAGAR, Under Secy.